

अधिकतम तापमान 24°C
न्यूनतम तापमान 18°C

बाजार

सोना 67,545

चांदी 77,600

संसेक्स 72,643

निफ्टी 22,023

सांक्षिप्त खबरें

सुप्रीम कोर्ट सीए पर 19 मार्च को करेगा सुनवाई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को नागरिकता संशोधन नियम 2024 (11 मार्च 2024 को अधिसूचित) के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की याचिका पर 19 मार्च को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डी वी चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओरपेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की गुहार स्वीकार करते हुए कहा कि मामले को मंगलवार के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें मामले को सूचीबद्ध करने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को नागरिकता पर मवाल उठाने का अधिकार नहीं है। इससे पहले केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर नागरिकता संशोधन नियम-2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने का निर्देश देने की गुहार लगाई थी। डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक अलग याचिका में नागरिकता संशोधन नियमों को संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि यह अस्थायिक, भेदभावपूर्ण, स्पष्ट रूप से मनमाना, अनुचित और तर्कहीन है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से सीए-2019 और नियमों के विरुद्ध संचालन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। इसकी दलील है कि धर्म के आधार पर भेदभाव करने के कारण सीए धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की जड़ पर हमला करता है, जो संविधान की मूल संरचना है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जीर्णोद्धार कार्यों का करेंगे लोकार्पण

भोजपुर। आर सांसद सह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह आर के हितनारायण क्षेत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण करेंगे। विद्यालय के जीर्णोद्धार के कार्य को टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के सीएसआर कार्य के अंतर्गत किया गया है। हितनारायण क्षेत्रिय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आर में सबसे पुराने और उत्तम विद्यालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ से पढ़कर निकलने वाले विद्यार्थियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। कुछ महीनों पहले विद्यालय के जर्जर हो चुके भवन को लेकर विद्यालय प्रबंधन ने सांसद सह केंद्रीय मंत्री श्री आर के सिंह से मुलाकात किया था। केंद्रीय मंत्री आज विद्यालय के जीर्णोद्धार कार्यों का लोकार्पण करेंगे।

ममता बनर्जी की हालत स्थिर, चेहरे पर लगे चार टांके

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चेहरे पर चार टांके लगे हैं और उनकी हालत स्थिर है। सुश्री बनर्जी को कालीघाट स्थित अपने घर में गिरने के बाद गुरुवार शाम एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल में चिकित्सकों ने उसके माथे पर तीन और नाक पर एक टांका लगाया तथा सीटी स्कैन सहित सभी आवश्यक परीक्षण किए। सूत्रों ने बताया कि उन्हें गुरुवार रात को छुट्टी दे दी गई। वह घर पर ही रहना चाहती थीं। सत्तारूढ़ तुणुमल कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि उसकी पार्टी अध्यक्ष को गंभीर चोट लगी है और उन्होंने तुरंत पीएचटी की जिसमें उनके सिर से खून बहता दिख रहा था।

नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार : राजभवन में राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 21 मंत्रियों को दिलायी शपथ

भाजपा कोटे से 12 व जदयू से 9 मंत्रियों ने ली शपथ

● शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुये मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री

प्रातः किरण

पटना। नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का विस्तार हो गया। राजभवन में शुक्रवार को आयोजित मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुये। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राजभवन स्थित राजेन्द्र मंडप में भाजपा कोटे से रेणु देवी, मंगल पाण्डेय, नीरज कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, डॉ दिलीप कुमार जायसवाल, जनक राम, हरि सहनी, कृष्णनंदन पासवान, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता एवं संतोष कुमार सिंह एवं जदयू कोटे से अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सहनी, महेश्वर हजारी, शीला कुमारी, सुनील कुमार, जयंत राज, मो जमा खान, रनेश सादा को मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

भाजपा कोटे 12 तथा जेडीयू से नौ मंत्रियों ने शपथ ली। बता दें कि नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को एनडीए के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ 8 मंत्रियों ने शपथ लिया था। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में 29 मंत्री हो गए हैं। इनमें 15 भाजपा से, 12 जदयू, एक हम और एक निर्दलीय मंत्री हैं। जदयू ने पुराने मंत्रियों पर जताया भरोसा जदयू ने अपने उन पुराने मंत्रियों पर फिर से भरोसा किया है जो महागठबंधन की सरकार में भी मंत्री थे। मंत्रिमंडल में जदयू कोटे से केवल एक नए नाम महेश्वर हजारी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। उन्हें संजय झा के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद खाली हुई सीट पर मंत्री बनाया गया है। उन्होंने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। भाजपा कोटे से मंत्री पद के लिए सात नए नाम : भाजपा कोटे से जो एक दर्जन मंत्री बने हैं उनमें सात नाम नए हैं।



इन्में नीतीश मिश्रा का नाम भी शामिल है। एनडीए के पिछले मंत्रिमंडल में नीतीश मिश्रा शामिल नहीं थे। वहीं, हरि सहनी, कृष्णनंदन पासवान, डा. दिलीप जायसवाल, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता व संतोष कुमार सिंह सभी पहली बार एनडीए सरकार में मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल का स्वरूप : भाजपा कोटे से- सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, डा. प्रेम कुमार, रेणु देवी, मंगल पांडेय, नीरज कुमार सिंह, नीतीश मिश्रा, नितिन नवीन, डा. दिलीप जायसवाल, जनक राम, हरि सहनी, कृष्णनंदन पासवान, केदार प्रसाद गुप्ता, सुरेंद्र मेहता एवं संतोष कुमार सिंह। जदयू कोटे से- विजय कुमार चौधरी, बिजेन्द्र प्रसाद यादव,

मंत्रिमंडल में भाजपा-जदयू ने साधे जातीय समीकरण

लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद की शपथ में बिहार की जातीय समीकरण को पूरा ध्यान रखा गया है। इनमें छह सर्वर्ण, छह अनुसूचित जाति, चार ओबीसी, चार पिछड़े वर्ग और एक मुस्लिम समुदाय के मंत्री हैं। मंत्री बनाकर नीतीश कुमार और बीजेपी ने सभी जाति और समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश की है। एनडीए सरकार में जमा खान एकलौते मुस्लिम मंत्री हैं, जिन पर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। भाजपा के सभी मंत्रियों पर गौर करने तो कुशवाहा से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को जगह मिली है। अति पिछड़ा से कुल तीन नाम हैं। जिसमें प्रेम कुमार, रेणु देवी, हरी सहनी, धानुक से एक सुरेंद्र मेहता, ब्राह्मण से दो यानी मंगल पांडेय और नीतीश मिश्रा, वैश्य से दो, डॉ. दिलीप जायसवाल और केदार गुप्ता को जगह मिली है। राजपूतों का भी ख्याल रखा गया है। राजपूत से दो लोगों को मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। जिसमें नीरज बबलू और संतोष सिंह शामिल हैं। दलित से दो लोग शामिल हैं। जिसमें कृष्ण नंदन पासवान और जनक राम को जगह दी गई है। कायस्थ से जितिन नवीन और भूमिहार समाज से उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को जगह दी गई है। कुल मिलाकर बीजेपी ने जातीय समीकरण को पूरी तरह साधने की कोशिश की है। मंत्रिमंडल में सर्वर्णों को बीजेपी की ओर से ज्यादा तरजीह दी गई है। हालांकि, सियासी जानकार मानते हैं कि बीजेपी ने पुराने चेहरे को जेडीयू की तरह रिपीट नहीं किया है। बीजेपी ने युवा और नए चेहरे पर विश्वास जताया है।

लव-कुश के साथ-साथ सवर्णों को साधने की कोशिश

नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी और फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही बीजेपी जातीय समीकरण पर पूरा फोकस कर रही है। नीतीश कुमार के साथ दो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को बनाया गया था। उसमें भी जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई थी। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति के हैं, तो सम्राट चौधरी कुशवाहा या कोइरी जाति के हैं। सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाकर लव-कुश (कुर्मी और कोइरी) को साधने की कोशिश की गई थी। इसी तरह से विजय सिन्हा भूमिहार जाति यानी सवर्ण जाति हैं। इस तरह से महत्वपूर्ण पद पर पिछड़े और सवर्ण का संतुलन बनाने की कोशिश की गई थी, ताकि कोई नाराज नहीं हो जाए। पिछली बार नौ मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी। इनमें भूमिहार जाति के 2, कुर्मी जाति के 2 मंत्री, राजपूत से एक, यादव जाति से एक मंत्री और पिछड़ा, अति पिछड़ा और महादलित के एक-एक मंत्री बनाए गये थे।

श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, महिलाओं की संख्या तीन : शुक्रवार शाम मदन सहनी, महेश्वर हजारी, शीला कुमारी, मंत्रीपद की शपथ लेने वालों में सबसे आगे सुनील कुमार, जयंत राज, जमा खान एवं रनेश सादा। हम कोटे से- डॉ. संतोष सुमन। निर्दलीय-सुमित कुमार सिंह मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या तीन : शुक्रवार शाम मंत्रीपद की शपथ लेने वालों में सबसे आगे सुनील कुमार, जयंत राज, जमा खान एवं नीरज कुमार बबलू ने शपथ लेने के बाद जय श्रीराम का जयघोष किया। भाजपा की रेणु देवी और जदयू की लेशी सिंह और शीला मंडल को मिलाकर इस मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या तीन हो गई। सरकार गठन के समय किसी भी महिला ने मंत्रीपद की शपथ नहीं ली थी।

सीएम नीतीश ने 20 योजनाओं का किया शुभारंभ व शिलान्यास



प्रातः किरण

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अग्रे मार्ग में रिमोट के माध्यम से शिलान्यास अनावरण कर 811 करोड़ रुपये की लागत की 20 योजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास किया। इन योजनाओं के अंतर्गत किसान कॉल सेंटर, आत्मा योजना, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की घेराबंदी, कृषि प्रसार योजना, कृषि यांत्रिकरण योजना, राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों की घेराबंदी, कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना, प्रति बूंद अधिक फसल योजना, बिहार पोषक अनाज (मिलेट्स) विकास योजना, बिहार मक्का विकास योजना, मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम, बीज योजनाएं (मुख्यमंत्री तीर्थ बीज विस्तार, प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम, बीज ग्राम योजना तथा धान बीज वितरण कार्यक्रम), केला क्षेत्र विकास योजना, प्याज, मखाना और अन्य उत्पादों का भंडारण, जैविक खेती प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत टैचा बीज वितरण, मशरूम किट का वितरण एवं झोपड़ी में मशरूम उत्पादन, शुष्क बागवानी योजना,

मखाना विकास योजना, कृषि ज्ञान वाहन, पान विकास योजना, सिंचाई विकास, आदर्श बागवानी केन्द्र (चाय), किशनगंज, उद्यमिक कलस्टर विकास योजना आदि से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 4 कृषि ज्ञान वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि ज्ञान वाहनों को रवाना करने के पहले मुख्यमंत्री ने कृषि ज्ञान वाहन के अंदर जाकर सारी व्यवस्थाओं एवं उपलब्ध उपकरणों की उपयोगिताओं की जानकारी ली।

ये रहे मौजूद : इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरात्रा, विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ, कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, निदेशक, उद्यान अभिषेक कुमार, निदेशक, बामेती आभांशु सौजन सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा आज

प्रातः किरण

नई दिल्ली/एजेंसी। निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कल यानी शनिवार को करेगा। निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए शनिवार को दोपहर तीन बजे एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है। पिछली बार लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा 10 मार्च को की गयी थी और 11 अप्रैल से सात चरणों में मतदान हुआ था। मतगणना 23 मई को हुई थी। नए निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने संभाषण प्रभार: नव नियुक्त निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने शुक्रवार को अपना प्रभार

संभाल लिया। दोनों पूर्व नौकरशाहों को बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया था।

व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में हाल में एक नया कानून लागू होने के बाद, निर्वाचन आयोग में नियुक्त किए गए पहले सदस्य हैं। एक प्रवक्ता ने बताया कि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का स्वागत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने ऐसे ऐतिहासिक समय पर उनकी नियुक्ति के महत्व के बारे में बात की जब निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव कराने की तैयारियां कर रहा है। अनूप चंद्र पांडे के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने और आठ मार्च को अरुण गोयल के अचानक इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग में ये पद खाली हो गए थे। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू दोनों वर्ष 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर से और सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड कैडर से आते हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 108 एजेंडों पर लगी मुहर कैबिनेट फैसला: राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता चार प्रतिशत बढ़ा

प्रातः किरण

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। जिसमें कुल 108 एजेंडों पर मुहर लगी। मंत्रिमंडल ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत वृद्धि करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। इसके साथ ही भागलपुर और राजगीर में सरकार नए हवाई अड्डे के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित कर निर्माण की सैद्धांतिक राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। राज्य के प्रमुख शहरों के आसपास नए सैटेलाइट टाउनशिप, ग्रीन फील्ड टाउनशिप विकसित किए जाएंगे। इस



आशय का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सप्तम केंद्रीय पुनर्रिक्त वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे सरकारी सेवक और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता में एक

जनवरी 2024 के प्रभाव से चार प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। इन्हें अब तक 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था अब 50, प्रतिशत भत्ता मिलेगा। इसके अलावा षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे सेवकों और पेंशनरों का भत्ता एक जुलाई 23 के प्रभाव से 221 प्रतिशत के स्थान पर 230 प्रतिशत करने का प्रस्ताव, पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर रहे सेवकों और पेंशनरों पहली जुलाई 2023 के प्रभाव से 412 के स्थान पर 427 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। उपभोक्ताओं के विद्युत अनुदान

को 15345 करोड़ : मंत्रिमंडल वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित अनुदान देने के लिए मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की अवधि के लिए 15345 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक के माध्यम से एनटीपीसी को देने को देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। प्रत्येक महीने इस मद में 1278.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे। मोड़नुलहक स्टेटियम के पुर्ननिर्माण के लिए बीसीसीआइ को देने की स्वीकृति : पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोड़नुलहक स्टेटियम के पुर्ननिर्माण के लिए भारतीय

क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआइ) को दीर्घकालीन लीज पर देने का प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किया है। इसके अलावा, प्रदेश के नौ प्रमंडलों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल संरचनाओं के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है। हर जिले में आग्रपाली प्रशिक्षण केंद्र, एथलीटों के लिए छात्रवृत्ति कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के लिए सभी जिलों में आग्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए वर्ष 2024-25 में 1086.60 करोड़ और 2025-26 में 934.80 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

बिहार सरकार

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय

(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

बिहार सर्वे ट्रेकर

जानिए विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की प्रगति और सुनिश्चित करें ऑनलाईन सहभागिता

बिहार सर्वे ट्रेकर द्वारा प्रदत्त सेवाएँ :-

- अपने जिला, अंचल एवं ग्राम के नाम का चयन कर जायें अपने ग्राम में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य एवं बन्दोबस्त की अद्यतन स्थिति, शिविर का पता एवं कार्यरत कर्मियों की जानकारी एवं मोबाईल नंबर |
- जानें उन राजस्व ग्रामों को जिनका प्रारूप अधिकार अभिलेख (ड्राफ्ट) एवं मानचित्र प्रकाशित कर दिया गया है।
- 11 प्रकार की ऑनलाईन उपलब्ध लोक सेवाओं यथा स्वघोषणा, खानापुरी पर्चा की प्राप्ति एवं आपत्ति का समर्पण, ड्राफ्ट पश्चात् आपत्ति देने की सुविधा, आपत्ति के विरुद्ध दिए गए आदेश को देखने की सुविधा, अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र देखने की सुविधा।
- खेसरावार निर्धारित किए गए लगान को देखने की सुविधा।
- अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार अभिलेख (स्वतियान) एवं मानचित्र को देखने की सुविधा।
- लोक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अपना नाम, राज्य एवं जिला का नाम, मोबाईल नं०, आधार नं० एवं यदि उपलब्ध हो तो ईमेल दर्ज कर रजिस्टर करें एवं लोक सेवाओं को प्राप्त करें।

(उपरोक्त सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए अपने एंड्रायड मोबाईल के प्ले स्टोर से बिहार सर्वे ट्रेकर एप डाउनलोड करें)

#BiharRevenueLandReformsDept

RevenueBihar BiharRevenue

पाकिस्तान बसाने को सीएए नहीं

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) की व्याख्या ही बदलने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, जो भावोत्तेजक हैं। उनकी मंशा हिंदू-मुसलमान से आगे बढ़कर आर्थिक संसाधनों और स्थितियों पर केंद्रित करने की है, ताकि राजनीति की दिशा और दशा बदली जा सके। हालांकि ऐसी संभावनाएं नाग्य हैं। संयुक्त राष्ट्र नागरिकता को व्यक्तिपरक सुरक्षा का बुनियादी तत्त्व मानता है और प्रताड़ित, शोषित, मानवाधिकार कुचलन के शिकार लोगों को शरणार्थी के तौर पर किसी भी देश में प्रवेश करने की मानवीय कर्म मानता है। संयुक्त राष्ट्र ऐसे अंतरराष्ट्रीय समझौते का भी जिन्न करता है, जिसके तहत शरणार्थियों को नागरिकता भी दी जा सकती है। केजरीवाल ने उत्तेजित अवस्था में कहा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भारत में बसाने का कानून बनाया गया है। कल हमारे देश में चोरियां, डकैतियां, बलात्कार होंगे। जगह-जगह दंगे भी भड़केंगे। देश की सुरक्षा-व्यवस्था का क्या होगा? केजरीवाल का आकलन है कि अब जो पलायन होगा, वह भारत-विभाजन से भी बड़ा और खतरनाक होगा। केजरीवाल के मुताबिक, तीनों पड़ोसी देशों से 2.5 करोड़ से अधिक लोगों का पलायन हो सकता है। भारत सरकार उन्हें कहां रखेगी? कहां घर देगी? कहां खाने को अनाज देगी? कितनी नौकरियां और रोजगार दिए जा सकेंगे? देश के आर्थिक संसाधन तो सीमित हैं। हमारे नौजवानों के लिए नौकरी, रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं और भाजपा ने देश के भीतर एक ओर पाकिस्तान को बसाने का कानून बनाया है। केजरीवाल ने सीएए को भाजपा का वोट बैंक तैयार करने की रणनीति करार दिया है।

बहरहाल केजरीवाल के अपने तर्क और राजनीति-शास्त्र हो सकते हैं। वह सीएए पर सांभदायिक उन्माद फैलाने वाली भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते, लिहाजा आर्थिक संसाधनों के आधार पर भावोत्तेजक राजनीति कर रहे हैं। विभाजन के दौर का वीरभक्त और त्रासद सरकारी आंकड़ा यह है कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश), अफगानिस्तान तीनों पड़ोसी देशों से 72 लाख के करीब लोगों ने पलायन किया था। हालांकि अनौपचारिक आंकड़े ये हैं कि तब 2 या 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने पलायन किया होगा ! ये आंकड़े विभिन्न संपत्तंत्रों और मीडिया प्रतिनिधियों ने जुटाए थे। भारत-विभाजन से ज्यादा खौफनाक घटनाक्रम उस दौर में कोई और नहीं हुआ।

दो रुपए की छूट और अरबों की लूट

आज भारत सरकार को धन्यवाद देने के साथ ही उसकी निंदा करने की भी दिना है। धन्यवाद इसलिए की उसने पूरे पांच साल लूटने के बाद जनता को डीजल और पेट्रोल के दमों में दो रुपए लीटर की छूट देने का ऐलान किया है और निंदा इसलिए की सरकार ने इलेक्टोरल बांड के जरिये पांच साल में 60 अरब का चन्दा ईडी की नोक पर वसूल लिया। ये दोनों ही बातें चूँकि तथ्यात्मक हैं इसलिए इन्हें लेकर आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको आने वाले दिनों में लुटेरी सरकार चाहिए या उसका कोई विकल्प। इसमें कोई दो राय नहीं की हमारी सियासत का दांचा लोकतांत्रिक है लेकिन इसमें लूट-खसोट की पूरी गुंजाइश है। पिछले 77 साल में जो भी सत्ता में आया उसने लोक कल्याण के साथ जितना बना देश और देश की जनता को लूटा। किसी ने कम लूटा तो किसी ने ज्यादा लूटा। किसी ने उदारता दिखाई तो किसी ने लूटने में पूरी निर्ममता का प्रदर्शन किया। केंद्रीय चुनाव आयोग की वेब साइट पर दशायें रुपए आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि आजादी के बाद कोई सबसे बड़ी लूट मौजूदा सत्ता ने की है। भाजपा की और मोदी की गरंटी वाली सरकार ने पांच साल में इलेक्टोरल बांड के जरिये दस-बीस लाख नहीं बल्कि पूरे 60 अरब रुपए देश के उद्योगपतियों से वसूल किये और वो भी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की नोक पर। आप कहेंगे कि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) कोई चाकू या तलवार तो नहीं है जो उसकी नोक होती हो, लेकिन हकीकत ये है कि इस संस्था की नोक इतनी पेनी है कि जिसकी भी गंदन पर रखी गयी उसने मन से या बेमन से इलेक्टोरल बांड खरीदकर भाजपा के खाते में डाल दिए। लूट का ये नायाब तरीका कांग्रेस छह दशक तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस भी नहीं खोज पायी थी। केंचुआ की वेब साइट पर आयी 762 पृष्ठों की जानकारी का सार ये है कि भाजपा ने पांच साल में कुल 60 अरब रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बाॅन्ड को भुनाया है। इस मामले में दूसरे नंबर पर तुणमूल कांग्रेस है, जिसने 16 अरब रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बाॅन्ड को भुनाया है। राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बाॅन्ड खरीदने वाली कंपनी प्रयुजर गैमिंग एंड होटल सर्विसेज है। इस कंपनी ने कुल 1368 बाॅन्ड खरीदे, जिसकी कीमत 13.6 अरब रुपये से अधिक रही। लुटेरों की सरतारा भाजपा अब यदि रसोई गैस पर 100 रुपए की और पेट्रोल -डीजल पर आपको दो रुपए लीटर की छूट दे रही है तो ये कोई अहसान नहीं बल्कि आने वाले आम चुनावों में आपको अनमोल वोट की सबसे सस्ती कीमत है। अब यदि देश की भोली जनता इस हकीकत को नहीं समझती तो उसका मालिक भगवान ही हो सकता है, कोई राजनीतिक दल नहीं। राजनितिक दल तो चोर-चोर मोसरे भाई हैं, कोई छोटा लुटेरा तो कोई बड़ा लुटेरा। लूटना सभी के डीएनए में शामिल है। देश की जनता का दुर्भाग्य है कि उसे इन्हीं लुटेरों के गिरोहों में से अपने लिए चौकीदार, सेवक, संरक्षक और भाग्य विधाता चुनना है।

मेरा या किसी दुसरे लेखक/पत्रकार का अनुभव मुफकिन है कि कम हो किन्तु रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के अनुभव से ही हमें सबक लेना चाहिये। खासतौर पर सत्ता के चुनाव के समय के आचरण को देखकर। चुनाव के मौसम में आखिर जनता के ऊपर उधारों। रियायतों की बरसात क्यों हो रही है? सरकार इतनी विनयवत क्यों है? क्यों झुक रही है? इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास इशारों में कहते हैं कि -नवन नीच की अति दुखदाई जिमि धनु, अंकुश, उराग, बिलाई मतलब साफ है। वे उदाहरण सहित समझा गए हैं कि जैसे धनुष, अंकुश, सांप और बिल्ली झुकती है तो दुःख ही देती है अर्थात जिसके स्वभाव में नीचता है वो जब भी झुकेगा आपको ऊपर धार करेगा, इसलिए ऐसे सभी तत्वों से सावधान रहना चाहिये। हमारी सत्ता में धनुष, अंकुश, सर्प और बिल्ली किसी न किसी रूप में विद्यमान है। आज यदि हनुव से इंकार कारती रही है। उन्हीं चुनाव के लिए अभी तक प्रत्याशियों की आने वाले दिनों में यही सत्ता आपको ऊपर कहर ढाने वाली है। कहर का रूप कुछ ही हो सकता है। इसे पहचानना आसान नहीं है। ये कभी धाराओं के रूप में होगा तो कभी अध्यादेशों के रूप में। कभी एक देश, एक विधान, एक निशा, एक भाषा, एक वेश के रूप में होगा तो कभी किसी दुसरे रूप में। फिलहाल तो चुनाव इस विनय की वजह हैं। आप कल्पना कीजिये कि जिस सरकार ने पांच साल में अकेले इलेक्टोरल बांड से 60 अरब कमा लिए वो सरकार महंगाई के जरिये आपको तो 1.60 अरब लूट रही और अब जब आम चुनाव सिर पर है तो आपको पेट्रोल-डीजल पर दो रुपए लीटर की छोट देकर या रसोई गैस सिलेंडर पर सी रुपए की छूट देकर बरगलाना चाह रही है। सत्तारूढ़ दल ने चुनावी चर्चे से जुटाई गयी रकम के जरिये देश भर में अपनी पार्टी के लिए 450 आधुनिक कार्यालय बना लिए, लेकिन भवन विहीन स्कूलों कि फिफ्र नहीं की। अस्पताल बनाने को प्रार्थमिकता नहीं दी। बहरहाल आम चुनाव के जरिये कानून हमें और आपको एक अवसर देता है कि हम इस लूट-खसोट करने वाली संस्था से अपना हिस्सा बराबर करें या इस लूट-खसोट को लगातार जारी रखें !इलेक्टोरल बांड के जरिये की गयी लूट के जरिये धन वसूली के मामले में दूसरे नंबर पर अखिल भारतीय कांग्रेस समिति है जिसने 14 अरब रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बाॅन्ड को भुनाया है। इसके बाद भारत राष्ट्र समिति ने 12 अरब रुपये और बीजू जनता दल ने 7 अरब रुपये से अधिक के इलेक्टोरल बाॅन्ड को बनाया है। इस मामले में पाँचवें और छठे नंबर पर दक्षिण भारत की पार्टियों डीएमके और वार्डएसआर कांग्रेस (यूवासेना) रही। इन पार्टियों के बाद तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, जनता दल (सेक्युलर), सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनसेना पार्टी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बिहार प्रदेश जनता दल (यूनाइटेड), झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम, शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गोमन्तक पार्टी, जम्मू और कश्मीर नेशनल फ्रंट्स, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नाम शामिल है। ये आंकड़े मैंने आपको इसलिए बताये ताकि आपको फैसला करने में मदद मिले। आपसब तो केंचुआ कि वेब साइट को खंगाल नहीं सकते। चुनावी साल में रहलता की बरसात में भीकरा जनता अंधे दुःख-दर्द को भुलकर क्या फैसला करती है ये तो जनता जाने लेकिन एक बात जरूर है की देश आजदी के बाद के सबसे गंभीर दौर से गुजर रहा है। देश को गर्वीबी, बेरोजगारी, बीमारी और शिक्षा के तमाम लक्ष्यों के साथ ही धर्मन्धत्ता से भी जूझना पड़ रहा है।

विचार मंथन

सीएए को समझे बिना मोदी सरकार पर कीचड़ उछालना केजरीवाल की बौखलाहट है



दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद के जरीवाल लगातार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लागू होने का बेहूदा, बेतुका एवं उच्छृंखल विरोध कर रहे हैं। व एवं अन्य विपक्षी दलों के नेता सीएए रूपी उजालों पर कालिख पोतने का प्रयास करते हुए आकाश में पैबन्द लगाना चाहते हैं और सख्त्र नाव में सवार होकर राजनीति-सागर की यात्रा करना चाहते हैं। इस तरह का विरोध समय एवं शक्ति का अपव्यय है तथा बुद्धि का दिवालियापन है। यह लोकतंत्र के मूल्यों को धुंधलाने एवं ध्वस्त करने की कुचेष्टा है। सीएए को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि अराजकता का माहौल निर्मित कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में लाखों की संख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू व सिख आने से चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ने की बात कहकर केजरीवाल ने इन लोगों की भावनाओं को आहत किया है।केजरीवाल के बयान भ्रामक, बेबुनियाद एवं विक्वसात्मक इसलिए है कि सीएए नये आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध एवं पारसी लोगों पर लागू ही नहीं होगा, बल्कि उसे वर्ष 2014 एवं उससे पहले आये ऐसे शरणार्थियों को सीएए के अन्तर्गत नागरिकता देने का कानून है। ऐसा करते हुए वे न केवल आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि अराजकता का माहौल निर्मित कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में लाखों की संख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू व सिख आने से चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ने की बात कहकर केजरीवाल ने इन लोगों की भावनाओं को आहत किया है।केजरीवाल के बयान भ्रामक, बेबुनियाद एवं विक्वसात्मक इसलिए है कि सीएए नये आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध एवं पारसी लोगों पर लागू ही नहीं होगा, बल्कि उसे वर्ष 2014 एवं उससे पहले आये ऐसे शरणार्थियों को सीएए के अन्तर्गत नागरिकता देने का कानून है। अब इससे नये लोगों के आने, बेरोजगारी बढ़ने एवं कानून-व्यवस्था चरमरा के प्रश्न कहां से आ गये? विपक्षी दल इस कानून के

वे एवं अन्य विपक्षी दलों के नेता सीएए रूपी उजालों पर कालिख पोतने का प्रयास करते हुए आकाश में पैबन्द लगाना चाहते हैं और सख्त्र नाव में सवार होकर राजनीति-सागर की यात्रा करना चाहते हैं। ऐसा करते हुए वे न केवल आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि अराजकता का माहौल निर्मित कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में लाखों की संख्या में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से हिंदू व सिख आने से चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ने की बात कहकर केजरीवाल ने इन लोगों की भावनाओं को आहत किया है।केजरीवाल के बयान भ्रामक, बेबुनियाद एवं विक्वसात्मक इसलिए है कि सीएए नये आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध एवं पारसी लोगों पर लागू ही नहीं होगा, बल्कि देश में वर्ष 2014 एवं उससे पहले आये ऐसे शरणार्थियों को सीएए के अन्तर्गत नागरिकता देने का कानून है। अब इससे नये लोगों के आने, बेरोजगारी बढ़ने एवं कानून-व्यवस्था चरमरा के प्रश्न कहां से आ गये? विपक्षी दल इस कानून के सन्दर्भ में कपट और झूठ का सहारा लेकर मिस तरह दुष्प्रचार में जुट गए हैं, वह केवल अप्रत्याशित ही नहीं, खतरनाक भी है। वोट बैंक की बेहद सख्ती, घटिया और गंदी राजनीति के चलते किया जा रहा यह खतरनाक एवं देश तोड़क दुष्प्रचार न केवल लोगों को बरगलाने, बल्कि उकसाने वाला भी है। इस तरह का विरोध समय एवं शक्ति का अपव्यय है तथा बुद्धि का दिवालियापन है। यह लोकतंत्र के मूल्यों को धुंधलाने एवं ध्वस्त करने की कुचेष्टा है। सीएए की मूल आत्मा को समझे बिना उसका विरोध करना एवं मोदी सरकार पर कीचड़ उछालना बौखलाहट का द्योतक है।



प्रश्न इसलिए, क्योंकि इस कानून का किसी राज्य सरकार से कोई लेना-देना ही नहीं। नागरिकता देना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। यह बुनियादी बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी समझनी होगी, क्योंकि उनकी ओर से भी यह कहा जा रहा है कि वह इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। यह हास्यास्पद एवं विरोधीभासी स्थिति है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के जरीवाल इस विचित्र नतीजे पर पहुंच गए कि नागरिकता कानून को अमल में लाकर केंद्र सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भारत लाकर उन्हें नौकरियां देने और उनके लिए घर बनाने का काम करने जा रही है।जबकि सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से किन्हीं नये अल्पसंखकों का भारत लाकर बसाने, उन्हें घर एवं नौकरी देने का कानून है ही नहीं। कोई भी यह समझ सकता है कि वह संकपी राजनीतिक कारणों से नागरिकता कानून की मममानी व्याख्या कर रहे हैं और इस तथ्य की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि यह कानून उक्त तीन देशों के अल्पसंखकों को बुलाकर नागरिकता देने का नहीं है।

केजरीवाल के बचकाने एवं बेहूदे बयानों से हिन्दू एवं सिख शरणार्थियों में काफ़ी गुस्सा देखा गया है। उन पर

घातक हो सकता है मायावती का अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्णय

मायावती इसके पहले भी कई बार लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी तरह के गठबंधन में शामिल होने से इंकार करती रही हैं। उन्होंने चुनाव के लिए अमी तक प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है जिसके कारण उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में हर राजनीतिक दल अधिक से अधिक सीटें हासिल करना चाहता है। इसलिए एनडीए और इंडिया गठबंधन में छोटे-बड़े दल शामिल होकर अपना राजनीतिक कद और हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में मायावती का किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना कई प्रश्न खड़े करता है। प्रश्न यह है कि क्या अकेले चुनाव लड़कर मायावती एनडीए और इंडिया गठबंधन को चुनौती दे पाएंगी? क्या मायावती को मरोसा है कि उनका वोट बैंक पूरी तरह उनका साथ देगा? क्या मायावती को लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबले में बसपा हावी रहेगी? क्या मायावती को इस बात का मरोसा है कि इंडिया गठबंधन की बजाय मुस्लिम मतदाता उनके साथ मजबूती से खड़े होंगे? क्या मायावती चुनाव नतीजों के हिसाब से रणनीति का खुलासा करेगी? क्या मायावती एकला चली की राह पर हैं या फिर वो जिस तरह से खामोश हैं उसके पीछे कोई बड़ा प्लान है? बसपा प्रमुख ने पिछले छह-सात महीने में अकेले चुनाव लड़ने की बात कई बार कही है, साथ ही यह भी कहा कि गठबंधन करने से उनको नुकसान होता है।



डॉ. आशीष वशिष्ठ

लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं।

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने फिर एक बार आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा की है कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती इसके पहले भी कई बार लोकसभा चुनाव के लिए किसी भी तरह के गठबंधन में शामिल होना से इंकार करती रही हैं। उन्हीं चुनाव के लिए अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है जिसके कारण उनके इंडिया गठबंधन में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। 2024 के आम चुनाव में राजनीतिक लिहाज से उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य में हर राजनीतिक दल अधिक से अधिक सीटें हासिल करना चाहता है। इसलिए एनडीए और इंडिया गठबंधन में छोटे-बड़े दल शामिल होकर अपना राजनीतिक कद और हैसियत बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में मायावती का किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनना कई प्रश्न खड़े करता है। प्रश्न यह है कि क्या अकेले चुनाव लड़कर मायावती एनडीए और इंडिया गठबंधन

बीजेपी के प्रति ज्यादा रझान देखा गया है।मायावती तीन बार भाजपा के सहयोग से यूपी को मुख्यमंत्री भी बन चुकी हैं। बसपा ने पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिल कर लड़ा था लेकिन सपा की सहायता से शून्य से 10 सीट पर पहुंचने के बाद ही उन्होंने तालमेल समान कर दिया था।इसमें कोई दो राय नहीं है कि बसपा का वोट बैंक भी खिसक रहा है। बसपा सुप्रीमो भले ही कहें कि गठबंधन से उनकी पार्टी को नुकसान होता है लेकिन सच्चाई तो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में गठबंधन का सबसे ज्यादा लाभ बसपा को ही हुआ था। वर्ष 1996 में बसपा ने 6 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, तब बसपा को 20.6 प्रतिशत मत मिले थे। वर्ष 1998 में बसपा को चार सीटें मिलीं और वोट प्रतिशत बढ़कर 20.9 प्रतिशत हो गया। वर्ष 1999 में बसपा को 14 सीटें मिलीं और मत 22.08 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2004 में सीटें बढ़कर 19 हो गईं और 24.67 प्रतिशत



विष्णु सरकार के फैसलों से किसानों के खिले चेहरे

लेकर उसे लागू भी कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में शामिल किसानों के हित से जुड़े मामलों को जिस तेजी से छत्तीसगढ़ सरकार ने अमल में लाया है, यह स्वगत योग्य है। छत्तीसगढ़ की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। इस भरोसे को राज्य सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। राज्य सरकार ने राज्य के 18 लाख से अधिक पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है। किसानों से प्रति एकड़ 21 किंवटल धान की खरीदी का भी गई है।किसानों का मानना है कि राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। राज्य के किसान भाईयों

को 2183 रूपए प्रति किंवटल के मान से समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घण्टे के भीतर उनके बैंक खातों में किया गया है।किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 24.72 लाख किसानों को धान के मूल्य के अंतर की राशि 13320 करोड़ रूपए का भुगतान का प्रदेशव्यापी शुभारंभ भी हो चुका है। भारत कृषि प्रधान देश है। देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और यह राज्य धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कहते है कि एक दौर ऐसा था जब किसानों के पास उन्नत और बेहतर

खेती के लिए पूंजी नहीं होती थी।किसानों को साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर रकम लेकर खेती-किसानी करनी पड़ती थी। किसान हमेशा कर्ज में फंसे रहते थे। इस स्थिति को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किसानों के हित में सबसे बड़ा कदम उठाया और किसान क्रेडिट कार्ड की योजना लागू की। इससे किसानों को कम दर पर सोसायटियों एवं बैंकों से कर्ज मिलने लगा। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में पहली बार भाजपा की सरकार बनी, उस समय सहकारी बैंकों से किसानों को रियायती ब्याज दर पर खेती के लिए कर्ज मिलता था, जिसे धीरे-धीरे घटाकर शून्य प्रतिशत कर

दिया गया।किसानों को बिना ब्याज के खेती-किसानी के लिए ऋण देने का काम छत्तीसगढ़ की रमन सरकार के दौर में शुरू हुआ था। आज भी किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर खेती के लिए लोन मिल रहा है। फसल लीमा जिसका लाभ पूरे देश के किसानों को सहजता से मिल रहा है। इसका श्रेय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। उनके कार्यकाल में ही फसल बीमा

जिला पदाधिकारी द्वारा लोक शिकायत के 10 मामलों की हुई सुनवाई



प्रातः किरण संवाददाता

छपरा कार्यालय। जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील से संबंधित शिकायतों की सुनवाई की गई और शिकायत का निवारण किया गया। जिला पदाधिकारी द्वारा शुक्रवार को लोक शिकायत के कुल 10 मामलों की सुनवाई की गई जिसमें 04 मामलों के संदर्भ में अंतिम रूप से आदेश पारित किया गया तथा शेष 06 मामलों में पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली तिथि को लोक प्राधिकार को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जिला पदाधिकारी अमन समीर ने कहा कि लोक शिकायतों का समयय तथा गुणवत्तापूर्ण निवारण अत्यावश्यक है। लोक प्राधिकारों को तत्परता प्रदर्शित करनी होगी। उन्होंने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आगामी होली त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक

प्रातः किरण संवाददाता

छपरा कार्यालय। आगामी होली के त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आज प्रमंडलीय आयुक्त श्री एम० सरवचन के अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई।

आयुक्त ने कहा कि इस वर्ष होली के साथ साथ चुनाव का भी समय है, इसलिए अतिरिक्त संर्तकता बरतने की आवश्यकता है।

उन्होंने सभी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को प्रीवेंटिव कार्रवाई पर विशेष बल देने को कहा। मद्य निषेध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया विदेशी शराब एवं रिस्पिट के परिवहन एवं बिक्री तथा देशी शराब के निर्माण, परिवहन एवं बिक्री के विरुद्ध कारगर आसूचना संकलन के आधार पर सघन छापामारी/जांच अभियान चलाने का



निर्देश दिया गया। दियारा के नदी क्षेत्रों में बोट पेट्रोलिंग के माध्यम से पेनी नजर बनाये रखने को कहा गया। होलिका दहन में अस्माजिक तत्वों द्वारा लकड़ी/पुस से निर्मित निजी संरचनाओं को भी होलिका में डालने की संभावना रहती

है, इस पर कड़ी नजर रखने को कहा गया। किसी भी व्यक्ति पर जबरन रंग/गुलाल डालने वाले लोगों के विरुद्ध भी त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित रखने को कहा गया। पूर्व के अनुभवों एवं अद्यतन आसूचना संकलन के

आधार पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से चिन्हित सभी संवेदनशील स्थलों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा गया। चुनाव के समय को देखते हुये सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अर्द्ध सैनिक बलों के सहयोग से निरंतर फ्लैग मार्च एवं पेट्रोलिंग करते रहने का निर्देश दिया गया। अद्यतन आसूचना संकलन के आधार पर अस्माजिक तत्वों को पहचान करते हुये उनके विरुद्ध कारगर निरोधक कार्रवाई करने का स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया प्रशासन सभी लोगों से शांतिपूर्ण एवं सद्भावपूर्ण वातावरण में होली एवं अन्य त्योहार को मनाने की अपील करता है। बैठक में पुलिस उपमहानिरीक्षक सारण श्री विकास वर्मन, जिलाधिकारी सारण श्री अमन समीर, पुलिस अधीक्षक सारण डॉ० गौरव मंगला तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिवान एवं गोपालगंज जिला के जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक जुड़े थे।

लोकसभा चुनाव: मास्टर ट्रेनर का प्रथम उन्मुखीकरण सह कार्यशाला आयोजित

प्रातः किरण संवाददाता

छपरा नगर. वृत्ति रहित और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराना प्रशासन का लक्ष्य है, इसका पूरा दायरामा मास्टर ट्रेनर पर है। उक्त बातें उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद अकबाल ने शुक्रवार को प्रेक्षागृह में आयोजित मास्टर ट्रेनर के प्रथम उन्मुखीकरण सह कार्यशाला को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने वार्तालाप विधि अमनते हुए कहा कि मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रतिनियुक्ति के साथ ही आप सभी सीधे चुनाव



आयोग के अधीन आ गए हैं। चुनाव की सफलता का आधार कर्मियों का प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण जितना अच्छा और सटीक होगा, चुनाव उतना ही सरस, सफल, स्वच्छ, पारदर्शी व वृत्ति रहित होगा। उन्होंने कहा कि आप सभी कर्मियों को सिखाने का कार्य

करेंगे। इसलिए आप अपने ट्रेनिंग को बोझिल होने की बजाय टूट्टी प्वाइंट और रुचिकर बनाएँ। अपने मस्तिष्क में चुनाव का पूरा सीन स्पष्ट रखें। उसके अनुरूप ही स्टेपनर जानकारी रखें। इवीएम की पूरी जानकारी, विभिन्न प्रपत्र भरने आदि में स्वयं दक्ष बनें। डूज एंड डाट्स की कंठस्थ रखें। उन्होंने चुनाव कर्मियों द्वारा किए जाने वाले प्रक्रिया को कुल छह भागों में विभक्त करते हुए प्रशिक्षण समय को विभक्त करने को बात कही। उन्होंने डिस्कशन पद्धति अपनाते हुए

प्रेजाइडिंग, पी-चन, पी-डू, पी-थी, माइक्रो ऑब्जर्वर के साथ ही मतगणना सहायक और सुपरवाइजर के कार्यों पर चर्चा करते हुए प्रशिक्षण में उनके कार्यों को बिन्दुवार समझाने की बात कही। प्रशिक्षण में रामाधर प्रसाद ने चुनाव प्रक्रिया, शुभ नारायण ओझा ने इवीएम, सुशील कुमार ने प्रपत्र, राजीव चौधरी और विनय प्रताप ने डूज एंड डाट्स की जानकारी दी। रिसोर्स पर्सन के रूप में मणिकांत तिवारी, अनिल शर्मा, रमेश चंदा, आफताब आलम आदि उपस्थित थे।

पुलिस ने शराब तस्करो के खिलाफ चलाया अभियान, बड़ी मात्रा में देशी शराब जब्त

प्रातः किरण संवाददाता

माँझी। गुरुवार की देर शाम माँझी थाना क्षेत्र के महम्मदपुर में माँझी थाना पुलिस ने शराब तस्करो के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में देशी शराब सहित शराब बनाने वाली सामग्री तथा उसमें प्रयुक्त उपकरण



भी जब्त किया है। इस सम्बंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष अमित कुमार रावै

ने बताया कि गुरुवार की देर शाम सूचना मिली थी कि शराब कारोबारी महम्मदपुर में देशी शराब की चुलाई तथा सप्लाई कर रहे हैं। जिसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में कुल 495 लीटर देशी शराब तथा दो हजार लीटर अर्द्ध निर्मित शराब

जब्त किया गया। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर शराब तस्करी निकल भागने में देशी शराब की चुलाई तथा सप्लाई कर रहे हैं। जिसपर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में कुल 495 लीटर देशी शराब तथा दो हजार लीटर अर्द्ध निर्मित शराब

सौम्या शालिनी को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की डॉक्टरल फेलोशिप

प्रातः किरण संवाददाता

छपरा कार्यालय। जय प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के इतिहास विभाग की शोध छात्रा सौम्या शालिनी का चयन प्रतिष्ठित भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की डॉक्टरल फेलोशिप के लिए हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर हुए चयन में सौम्या शालिनी को 36वा स्थान प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व सौम्या शालिनी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में लगातार चार बार सफलता प्राप्त किया है। सौम्या शालिनी मूलतः परसा प्रखंड के बहलोलपुर



निवासी अधिवक्ता श्री जीवनन्दन शर्मा और सीमा की पुत्री हैं। बचपन से ही होहार विद्यार्थी रही सौम्या ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा छपरा के ए.एन.डी. पब्लिक स्कूल से करने के पश्चात पटना वीमेंस कॉलेज से इतिहास में स्नातक और पटना विश्वविद्यालय से परास्नातक की शिक्षा प्राप्त की है।

सौम्या वर्तमान में इतिहास विभाग जय प्रकाश विश्वविद्यालय में "ब्रिटिश भारत से मॉरिशस में अनुबंधित श्रम प्रवासन एवं भोजपुरी लोक संस्कृति का प्रसार" विषय पर शोध कर रही हैं। सौम्या की सफलता पर इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो० सुधीर कुमार सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सौम्या के उज्ज्वल भविष्य की कामना किया है। इसकी सफलता परिवार के सदस्यों के साथ विश्वविद्यालय के प्रो० संवेद राजा, प्रो० कृष्ण कन्हैया, प्रो० राजेश नायक, प्रो० दिव्याशु कुमार, डॉ० रितेश्वर प्राण तिवारी, डॉ० अभय कुमार सिंह और डॉ० श्याम प्रकाश ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बधाई दिया है।

विभाजनकारी कानून सीएए के खिलाफ आइसा ने किया प्रदर्शन

प्रातः किरण संवाददाता

छपरा सदर। शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया सीएए कानून को असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण एवं विभाजनकारी बताते हुए व 14मार्च को सी ए ए के विरोध में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान आइसा नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ आइसा सारण के कार्यकर्ताओं ने अपने देशव्यापी प्रतिवाद कार्यक्रम के तहत जयप्रकाश विश्वविद्यालय के गेट पर विरोध जताया। सभा को संबोधित करते हुए आइसा प्रदेश सहसचिव सह जिला सचिव दिपंकर मिश्र ने कहा कि दिसम्बर 2019 में पास किये गये भेदभावकारी और विभाजनकारी अन्यायपूर्ण



नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने वाली नियमावली की अधिसूचना 2024 चुनावों की अधिसूचना आने से ठीक पहले जारी करना एक राजनीतिक साजिश का संकेत है। जैसा कि अमित शर्मा ने खुद सीएए की 'क्रोनोलॉजी' समझाते हुए कहा था कि इस कानून को लागू करने के बाद एनआरसी-एनपीआर को देशव्यापी स्तर पर लाया

जायेगा जिसके माध्यम से दरतावेज न दिखाने वाले नागरिकों को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। सीएए नागरिकों को धर्म के आधार पर बांटने के मकसद से लाया गया है, जो भ्रामक रूप से 'गैरसुर्भ्रम' शरणार्थियों को नागरिकता देने और मुसलमानों की नागरिकता छीनने, यहाँ तक कि देशनिकाला देने, तक की बात करता है।

लेकिन असम में को गयी एनआरसी की कवायद और देश में जगह-जगह चलाये जा रहे बुलडोजर ध्वस्तिकरण अभियानों से स्पष्ट हो चुका है कि आदिवासियों और वनवासियों समेत सभी समुदायों के गरीब इंसानों से प्रभावित होंगे। देश का लोकतांत्रिक अभिमत और सभ्य नागरिकता एवं संवैधानिक अधिकार आन्दोलन ने सीएए-एनआरसी के पूरे पैकेज को संविधान पर हमला बता कर खाजिर कर दिया है। चुनाव से पहले सीएए नियमावली की अधिसूचना ने लोकतंत्र के संवैधानिक आधार को धमके के जलआन्दोलन की अनिवार्यता को पुनः रेखांकित किया है। मोदी सरकार को आगामी आम चुनावों में सत्ताच्युत करना जरूरी हो गया है।

अज्ञात युवक का शव माँझी थाना पुलिस ने किया बरामद

प्रातः किरण संवाददाता

माँझी। छपरा बलिया रेल खण्ड पर अवस्थित माँझी रेलवे हाट्ट के समीप रेल परिसर के गड्ढे में पड़े एक अज्ञात युवक का वीरस शव शुक्रवार को माँझी थाना पुलिस ने बरामद किया है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अज्ञात युवक का शव माँझी रेलवे हाट्ट से लगभग दो सौ मीटर उत्तर तथा रेल लाइन से लगभग एक सौ मीटर पुरब एक गड्ढे में पिछले चार पाँच दिनों से पड़ा हुआ था। शुक्रवार की सुबह खेत में लगी फसल काटने जा रहे मजदूरों ने दुर्गम आने पर शव को नजदीक जाकर



देखा और शोर मचा कर इसकी सूचना अन्य लोगों को दी। सूचना पाकर घटना स्थल पर पहुँचे माँझी के थानाध्यक्ष अमित कुमार राम ने घटनास्थल को तहकीकात के बाद इस बात की आशंका जताई की अपराधकर्मियों द्वारा युवक को हत्या कर साक्ष्य को छिपाने के उद्देश्य से शव को सुनसान स्थान पर फेंक दिया गया है। मृतक काले रंग की पैंट तथा गाढ़ा नीले रंग का टीशर्ट

एवम लाल रंग का गंजी पहने हुए था। शव के लगभग चार पाँच दिन पुराना होने की पुलिस ने आशंका जताई है। कोई दिन पुराना होने की वजह से शव के कुछ हिस्सों को कौवा व कुत्ते नोच रहे थे तथा उसके सड़ांध की बदसू से शव उठाने में पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मृतक का चेहरा भी पहचान के लायक नहीं बचा था। साथ ही उसकी जीब से ऐसा कोई भी कागजात अथवा परिचय पत्र आदि नहीं मिला जिससे उसकी पहचान की जा सके। बाद में जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी कर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा

भेज दिया। मृतक के शव से महज कुछ ही दूरी पर खाली पड्डी पाँच अंग्रेजी शराब की बोतलें, होटल से खरीदी गई पैकिंग मीट के दो खाली डिब्बे, सिगरेट के खाली दो डिब्बे, तथा पतल व प्लास्टिक के गिलास को पड़ा हुआ देखकर पुलिस ने आशंका व्यक्त की है कि युवक के अलावा आठ दस लोगों ने सुनसान स्थान पाकर पहले पार्टी की होगी तथा किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद उसकी हत्या की गई होगी। पूछे जाने पुलिस सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही हत्याकांड के असली कारणों का पता लगाया जा सकेगा।

आयुष्मान भारत कार्ड वितरण शिविर आयोजित

प्रातः किरण संवाददाता

छपरा कार्यालय। परसा प्रखंड के बहमार पंचायत के बहमार में उप सरपंच लालू सिंह के घर पर आयुष्मान भारत कार्ड वितरण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश कार्य समिति सदस्य सह सांसद प्रतिनिधि राकेश सिंह क्षेत्रीय प्रभारी अनिल सिंह उपस्थित रहे।



सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी जी के सौजन्य से कुछ दिन पहले के प लगाकर लगभग 102 लोगों

का पंचायत में निशुल्क कार्ड बनाया गया था जिससे आज सभी लाभुकों को कार्ड का निशुल्क वितरण किया गया। कार्ड मिलने पर लाभुकों ने सारण सांसद को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब कोई भी गरीब पैसों के अभाव में बीमारी के इलाज के लिए लाचार नहीं रहेगा। और सारण सांसद के इस

महवतकांशी योजना के लिए आभार प्रकट किया। इस अवसर पर भाजपा नेता जीतेन्द्र सिंह सरोज राय संतोष शर्मा कप्तान साहब युवा मोर्चा कुणाल कुमार सुमंत कुमार सोनु सिंह प्रियाशु सिंह हरेश राम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे सभी लोगों ने इसके लिए धन्यवाद दिया।

होली को ले चलेगी विशेष ट्रेन

छपरा कार्यालय। रेलवे प्रशासन द्वारा होली त्योहार पर हो रही यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हेतु 05051/05052 छपरा-गंगा नवासी बरतन बन्द का पुत्र अभिल नट व कमल राउत का पुत्र सतेन्द्र कुमार बताया जाता है। इस संबंध थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया पूरे छपरा से 180 एमएल के अंग्रेजी शराब के दो फ्रूटी व 20 लीटर देशी शराब के साथ शराब धंधेबाज कोशल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। व पड्डी मुजौना में शराब पीकर हंगामा कर रहे दो शराबी को गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार व्यक्ति पर उदाय अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है।

09.10 बजे, बस्ती से 09.39 बजे, गोंण्डा से 11.05 बजे, ऐषबाग से 13.43 बजे, कानपुर सेन्ट्रल से 15.10 बजे, ऊरई से 16.42 बजे, वीरगंगा लक्ष्मीबाई जं. से 18.53 बजे, भोपाल से 23.15 बजे, दूसरे दिन इटारसी से 00.55 बजे, नागपुर से 06.45 बजे, बल्हारषाह से 10.05 बजे, सिरपुर कागजनगर से 10.57 बजे, बेल्जमपल्ली से 11.32 बजे, रामगुंडम से 12.01 बजे तथा काजीपेट से 13.27 बजे झूटकर सिकन्दराबाद 16.35 बजे पहुँचेगी। वापसी यात्रा में 05052 सिकन्दराबाद-छपरा होली विशेष गाड़ी 01 अप्रैल, 2024 दिन सोमवार को सिकन्दराबाद से 08.30 बजे, खलीलाबाद से

प्रस्थान कर काजीपेट से 23.00 बजे, दूसरे दिन रामगुंडम से 00.32 बजे, बेल्जमपल्ली से 01.07 बजे, सिरपुर कागजनगर से 01.32 बजे, बल्हारषाह से 03.20 बजे, नागपुर से 06.35 बजे, इटारसी से 12.00 बजे, भोपाल से 13.50 बजे, वीरगंगा लक्ष्मीबाई जं. 21.20 बजे, ऊरई से 22.22 बजे, तीसरे दिन कानपुर सेन्ट्रल से 01.30 बजे, ऐषबाग से 02.50 बजे, गोंण्डा से 05.45 बजे, बस्ती से 07.20 बजे, खलीलाबाद से 07.52 बजे, रामगुंडम से 09.05 बजे, कप्तानगंज से 10.10 बजे, पडरौना से 10.47 बजे, तमकुही रोड से 11.20 बजे, थावे से 12.10 बजे तथा सीवान से 13.10 बजे झूटकर छपरा 14.20 बजे पहुँचेगी।

शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए शहरवासी अपना सुझाव दें : मेयर

छपरा। आगामी बजट को लेकर नगर निगम के मेयर लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने शहर वासियों से सुझाव मांगे हैं ताकि छपरा शहर को एक सुंदर शहर बनाया जा सके। आज अपने कक्ष में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि शैक्षणिक पर्यावरण आधारभूत संरचनाओं आदि किसी भी क्षेत्र में छपरा के लोगों के पास शहर को संवराने का सुझाव है तो वे मुझे व्हाट्सएप कार्यालय या घर पर दे सकते हैं उनके सुझावों पर विचार किया जाएगा, श्री गुप्ता ने कहा कि छपरा को स्वच्छ सुंदर बनाना चाहता हूँ इसके लिए आप सबों का सहयोग जरूरी है। शहर में एंजेंसी द्वारा बेहतरास टैक्स लिए जाने पर उन्होंने कहा कि हर वार्ड में फ्लेक्स के माध्यम से टैक्स की जानकारी सार्वजनिक रूप से दी जाएगी, उस हिसाब से ही लोग अपना टैक्स जमा करें अभी पुराने धरें पर ही टैक्स का वसूली किया जा रहा है अगर एंजेंसी के द्वारा पैसा की उगाही की जा रही तो वह मुझे शिकायत करें मैं पूरी तरह छपरा जनता के साथ हूँ और रहूँगा, वही विस्थापित दुकानदारों के विषय में उन्होंने कहा कि उन्हें स्थापित करने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं।

राशिका हेरा फेरी करने के मामले में प्राथमिकी

परसा।थाना रोड में संचालित सेंट्रल बैंक के सीएसपी से राशिका हेरा फेरी करने का मामला प्रकाश में आया है जिसको लेकर थाना क्षेत्र के बहर मराड़ निवासी स्व रवि कांत मिश्रा की पत्नी संजू देवी द्वारा थाना में संचालित पर प्राथमिकी दर्ज करवाया है। प्राथमिकी में बताया गया है कि संचालक थाना क्षेत्र के बहर मराड़ निवासी राशिका अमन द्वारा थाना रोड में सेंट्रल बैंक का सीएसपी चलाता था जिसमें पीछे दिखलाल मल्लिक संजू देवी द्वारा 5 फरवरी को 49 हजार रुपये जमा किया गया था। जब राशिका का निकासी करने गई तो खाता में राशिका जमा नहीं था जिससे महिला अवक रह गई। और इसकी सूचना परिजनों को दिया।

शहर इन्फिनिटी इंटरनेशनल स्कूल का हुआ शुभारंभ

परसा। नगर पंचायत परसा बाजार अंतर्गत महमदपुर वस्ती में भारत इन्फिनिटी इंटरनेशनल स्कूल का शुभारंभ किया गया। नए स्कूल का उदघाटन मुख्य अतिथि डा.प्रो.अनिल कुमार, प्रो. सतीश कुमार, प्रो.विकास और अनिल, प्रो.चंदन प्रकाश, प्रो. मिथलेश कुमार, निर्देशक नन्द किशोर साह ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस अवसर पर वरीय शिक्षक विदेशवरी सिंह ने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा का अलख जगाने के उद्देश्य से इस विद्यालय को खोला गया। वही इस विद्यालय में बच्चों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। वही छोटे छोटे बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाएगा ताकि उनका शिक्षा जगत के साथ साथ मानसिक विकास भी हो सके। मौके पर वरीय शिक्षक शिवचसन राय, अनिश कुमार, दीपक कुमार अर्जुन कुमार, मुन्ना कुमार मौजूद थे।



संक्षिप्त समाचार

यूपी के प्रेमी ने की थी पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या

रायपुर, एजेंसी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के विधानसभा थाने में दर्ज पुलिसकर्मी की पत्नी की हत्या के मामले की गुन्थी की पुलिस सुलझाने में सफल हो गई है। पुलिस ने इस मामले में जांच करते हुए उत्तर प्रदेश से एक आरोपी को गिरफ्तार कर रायपुर ले आई है। सोशल मीडिया चैट से पता चला है कि आरोपी मृतक महिला का आशिक है। बता दे कि बीते दिनों रायपुर में महिला की अंधे कल्ले के मामले में पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। महिला के सोशल मीडिया अकाउंट को लगातार पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा था। जांच में यह पता चला कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले जय सिंह नाम के व्यक्ति के साथ महिला की बातचीत होती थी। पुलिस ने जांच में पाया कि जय सिंह ने ही महिला की हत्या की है। बताया जा रहा है कि महिला और जय सिंह के बीच प्रेम संबंध गहरे हो गए थे। जिसके बाद मृतक महिला आरोपी को शादी करने का दबाव बना रही थी, जिसके चलते उसने हत्या कर दी है। आपको बता दें कि महिला पहले से शादीशुदा थी। उसका विवाह शिवपाल सिंह के साथ हुआ था। शिवपाल सिंह जोकि सुकमा में पुलिस विभाग में पदस्थ है। दोनों पति-पत्नी के बीच आपसी अनबन होत के कारण दोनों साथ नहीं रहते थे। पति शिवपाल सिंह सुकमा में रहता था, तो पत्नी रायपुर में रहा करती थी।

गेहूँ की फसल के बीच 104 किलो से ज्यादा अफीम के पौधे किए जळ

ऊधमसिंह नगर, एजेंसी। उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में पुलिस ने गेहूँ की फसल के बीच से 104 किलो से अधिक के अफीम के हरे-भरे पौधे जळ किए हैं। साथ ही एक तस्कर को भी हिरासत में लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक, मुखबिर की सूचना पर पुलिस जयपुर उधम सिंह नगर गंगापुर थाना केलाखंड में दलजीत सिंह (उम्र 60 वर्ष) के घर के पास वाले खेत में पहुंची तो पाया कि गेहूँ के पौधों के बीच अफीम के हरे पौधे और डोडा फल उगाए गए थे। पुलिस ने लगभग 104.205 किलोग्राम अफीम और डोडा फल जब्त कर दलजीत के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

पंजाब में गैंगस्टर के दो सहयोगी गिरफ्तार

चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुरप्रीत लेखर और जस्सा नूरवाला गैंग के दो सहयोगियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान जगदीप सिंह उर्फ रिंकू और बलविंदर सिंह उर्फ बब्बू के रूप में हुई है। यह गिरोह कई जघन्य अपराधों में संलिप्त रहा है, जिसमें हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और वसूली शामिल है। पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह लुधियाना, जगराओ, मोगा, बटिंडा और संगरूर जिलों में सक्रिय रहा है। बता दें कि आरोपी रिंकू के खिलाफ मोगा में हत्या की कोशिश के मामले में केस दर्ज कराया जा चुका है।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या

बलौदा बाजार, एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में गुरुवार की सुबह एक कांग्रेसी नेता की हत्या कर दी गई है। कांग्रेस नेता को बार-बार ट्रैक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतारा गया है। कांग्रेस नेता दयाराम जायसवाल सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए थे। उस दौरान दयाराम को अकेला पाकर पहले ट्रैक्टर से ठोकर मारी गई फिर बार-बार ट्रैक्टर से कुचला गया है। क्या पूरा मामला कसडोल विधानसभा क्षेत्र के ग्राम असनीद का बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दयाराम जायसवाल की लाश को सड़क किनारे देखा गया था। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर ही कांग्रेस नेता की मौत हो चुकी थी। वहीं जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो पुलिस ने पूछताछ करते हुए आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में यह पता चला है कि यह पूरी हत्या की वजह जमीन और खेती के विवाद को बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांचकारी और आरोपी से पूछताछ के बाद बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

पार्किंग से उठी चिंगारी ने तबाह किया परिवार, शास्त्री नगर की चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग; 4 की मौत

नईदिल्ली, एजेंसी। दिल्ली के शास्त्री नगर के सरोजनी पार्क स्थित चार मंजिला इमारत में गुरुवार सुबह आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई। हादसे में पूरा परिवार तबाह हो गया। शाहदरा जिला पुलिस उपयुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गीता कॉलोनी थाने में तड़के करीब साढ़े पांच बजे एक घर में आग की पीसीआर कॉल मिली थी। कॉलर ने बताया कि शास्त्री नगर के सरोजनी पार्क इलाके में आग लगी है। सूचना पर मौके पर अग्निशमन की चार गाड़ियां, एंबुलेंस, स्थानीय पुलिस और तीन पीसीआर वैन पहुंची। चार मंजिला रिहायशी इमारत के भूतल पर पार्किंग और एक अन्य फ्लैट है। आग पार्किंग में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी और धीरे-धीरे पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया।

आग के बाद इमारत में मच गई अफरातफरी

पूरी इमारत में धुंआ भर गया, जिसके चलते लोगों में अफरा-तफरी मच गई। इमारत के अन्य तलों पर रहने वाले लोग छत की ओर भागे और अपनी जान बचाई। इसके चलते उनको मामूली चोटें आईं और



इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं, मनेज का परिवार भूतल पर यानि सबसे नीचे था और आग भी वहीं से शुरू हुई थी। इसके चलते उन्हें संभलने का मौका नहीं मिल पाया और धुएं और आग की चपेट में आने के चलते पहले परिवार के लोगों का दम घुटने के चलते उनकी मौत हो गई। इस दौरान आग ने भी काफी

विकराल रूप ले लिया।

पहले भी कई घटनाएं हो चुकीं

वजीराबाद पुलिस ट्रेनिंग स्कूल स्थित मालखाने की पार्किंग में 29 जनवरी को भयंकर आग लग गई। आग की चपेट में आने के चलते यहां खड़ी 250 से ज्यादा कारें जल गई थीं।

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के रेट में डबल कटौती, 7 रुपए तक हुआ सस्ता

जयपुर, एजेंसी। होली से पहले राजस्थान के लोगों को मंहगाई के मोर्चे पर बड़ी खुशखबरी मिली है। लंबे इंतजार के बाद पेट्रोल-डीजल की कीमत में कमी की गई है। एक ही दिन में राज्य और केंद्र सरकार की ओर से की गई कटौती की वजह से राजस्थान में कीमतें सबसे ज्यादा कम हुई हैं। गंगानगर में तो पेट्रोल 7.13 रुपए लीटर सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार ने जहां पेट्रोल और डीजल की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की है तो भजनलाल सरकार ने 2 पैसेट वेट घटा दिया है। राजस्थान में डीजल पर वेट पर 19.30 फीसदी से घटकर 17.30 फीसदी रह गया है तो पेट्रोल पर अब 29.04 फीसदी वेट लगना जो पहले 31.04 फीसदी था। वेट के दरों में कटौती की वजह से अलग-अलग शहरों में पेट्रोल 1.40 रुपए 5.30 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता होगा तो डीजल 1.34 रुपए से 4.85 रुपए सस्ता हुआ है। नई दरें

शुक्रवार सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई हैं। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की जनता से वादा किया था कि यदि राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने चुनावी रैलियों में भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों से राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों की तुलना की थी। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान और केंद्र सरकार ने कटौती करके राज्य के करोड़ों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। डबल कटौती के बाद जयपुर में पेट्रोल 3.60 रुपए लीटर हो गया है तो डीजल पर प्रति लीटर आपको 3.40 रुपए कम खर्च करने पड़ेंगे। जयपुर में गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपए प्रति लीटर थी जो अब घटकर 104.88 रुपए हो गई है। वहीं, डीजल की कीमत 93.72 रुपए प्रति लीटर से घटकर 90.32 रुपए लीटर रह गई है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना चाहते हैं इस्लामी चरमपंथी; यह लोकतंत्र के लिए खतरा- ब्रिटेन सरकार

लंदन, एजेंसी। पिछले साल सात अक्टूबर को इस्लाम पर आतंकी संगठन हमास के हमलों के बाद से बढ़ते खतरों और इस्लामी चरमपंथ के खिलाफ ब्रिटेन सरकार ने नई परिभाषा जारी की। ब्रिटेन में उग्रवाद को अब हिंसा, घृणा या असहिष्णुता पर आधारित विचारधारा के रूप में परिभाषित किया गया है।



यूके लेवलिंग अप और कम्युनिटी सेक्टरों में माइकल गोव ने कहा कि ब्रिटेन को एक बहु-राष्ट्रीय, बहु-जातीय, बहु-विश्वस्य लोकतंत्र के रूप में सुशिक्षित रखने के लिए अपडेट करने की जरूरत थी, जो इसकी विविधता को मजबूत करेगा। उन्होंने विस्तारित परिभाषा के तहत चरमपंथ विचार रखने की आशंका वाले लोगों के उदाहरण के रूप में तीन इस्लामिक समूहों और दो अन्य समूहों का

नाम लिया। उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर के हमलों के बाद चरमपंथी विचारधाराओं की वृद्धि हुई। जिसके चलते हमारा लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के विचारधारा वाले लोग लोगों को कट्टरपंथी बनाना चाहते हैं। लोगों को उनके पूर्ण अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना

अमेरिका में बढ़ रहा है हिंदू फोबिया, इससे लड़ने की जरूरत- अमेरिकी सांसद

वाशिंगटन, एजेंसी। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद श्री थानेदार ने कहा है कि हाल ही में अमेरिका में हिंदू फोबिया में वृद्धि देखी गई है, जिससे लड़ने की जरूरत है क्योंकि इस देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। थानेदार ने हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ते घृणा अपराध से लड़ने की मांग करने वाले हिंदू नेताओं और संगठनों के एक समूह में शामिल होने के अवसर पर यह बात कही। हिंदूत्वशान नामक संगठन द्वारा आयोजित एक बैठक के दौरान विभिन्न भारतीय अमेरिकी समूहों के प्रतिनिधियों ने बुधवार को अमेरिका की राजधानी में मुलाकात की। थानेदार ने कहा, " हम अमेरिका में बहुत अधिक हिंदू फोबिया (हिंदुओं को लेकर एक प्रकार की असुरक्षा की भावना) देखते हैं। हमने कैलिफोर्निया एसबी403 (जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक) देखा है, और यह तो बस शुरुआत है। हमारे मंदिरों पर हमले और दुनिया भर में हिंदुओं पर हमले। यही एक कारण है कि मैंने हिंदू कॉकस बनाने का फैसला किया है। अमेरिकी कांग्रेस में पहली बार, हमारे पास एक हिंदू कॉकस है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहल कर रहे हैं कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने की धार्मिक स्वतंत्रता हो जिस तरह से वे चाहते हैं।

अमेरिका में बढ़ रहा है हिंदू फोबिया, इससे लड़ने की जरूरत- अमेरिकी सांसद

चाहते हैं। गौरतलब है कि 2023 में इस्लाम में हमास के आतंकवादी हमलों के बाद से सरकार ने कहा कि चरमपंथी के जोखिमों के बारे में चिंताएं उठाई गई हैं। कम्युनिटी सिक्वैरिटी ट्रस्ट ने 2023 में हुए हमलों के बाद से ब्रिटेन में 4,103 यहूदी विरोधी घटनाएं दर्ज कीं, जो अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना

ऑस्ट्रिया ने रूस के दो राजनयिकों को निकाला

विएना, एजेंसी। ऑस्ट्रिया ने बुधवार को कहा कि उसने राजधानी विएना में स्थित रूसी दूतावास के दो राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। एक ऑस्ट्रियाई अधिकारी ने बताया कि दोनों राजनयिकों को जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के चलते निष्कासित किया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक संक्षिप्त बयान जारी कर बताया कि रूस के दो राजनयिक पद पर रहते हुए असंगत कृत्य में शामिल थे, इसलिए उन्हें निष्कासित किया गया है।



उन्होंने राजनयिकों या उनके कथित कार्यों के बारे में कोई और विवरण नहीं दिया। राजनयिकों ऑस्ट्रिया छोड़ने के लिए 19 मार्च तक का समय दिया गया है। मामले की जानकारी रखने वाले एक ऑस्ट्रियाई अधिकारी ने कहा कि राजनयिकों को जासूसी के आरोप में देश से निष्कासित किया गया है। अधिकारी ने नाम न छपाने की शर्त पर इस बारे में जानकारी साझा की है।

ऑस्ट्रिया में रूसी दूतावास ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान जारी कर कहा कि वह रूसी दूतावास के दो कर्मचारियों को देश से निकालने के ऑस्ट्रिया विदेश मंत्रालय के फैसले से नाराज है। रूसी दूतावास की ओर से जारी किये गये बयान में कहा गया है "हमारे राजनयिकों को निकालने के बारे में किसी भी प्रकार का कोई सबूत पेश नहीं किया गया। राजनयिकों द्वारा विनया कन्वेंशन का उल्लंघन करने के बारे में भी सबूत नहीं दिया गया है। यह ऑस्ट्रियाई अधिकारियों का पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय है।

अगर यूरोप शांति चाहता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन

पेरिस, एजेंसी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने कहा कि अगर यूरोप शांति चाहता है तो उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रूस को एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी कहा जो दो साल पुराने संघर्ष में कीव के सैनिकों को हराने के बाद भी यूक्रेन में नहीं रुकेगा। मैक्रॉन ने फरवरी में यह कहकर विवाद पैदा कर दिया था कि वह भविष्य में यूक्रेन में जमीनी सैनिकों की तैनाती से इनकार नहीं कर सकते, कई नेताओं ने खुद को इससे दूर कर लिया, जबकि अन्य, विशेष रूप से पूर्वी यूरोप ने समर्थन व्यक्त किया। अगर रूस यह युद्ध जीता है, तो यूरोप की विश्वसनीयता शून्य हो जाएगी, मैक्रॉन ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा, जो ज्यादातर धरूल दर्शकों के लिए था। मैक्रॉन ने कहा कि वह विपक्षी नेताओं से गहराई से असहमत हैं। उन्होंने कहा, आज, यूक्रेन को समर्थन देने के खिलाफ वोट देने या अनुपस्थित रहने का निर्णय, यह शांति नहीं चुन रहा है, यह हार चुन रहा है। यह अलग है। मैक्रॉन की मुख्य विपक्षी पार्टी, मरीन ले पेन की धुर दक्षिणपंथी पार्टी, फ्रांस द्वारा यूक्रेन के साथ हस्ताक्षरित सुरक्षा समझौते के बारे में सहाह की शुरुआत में संसद में मतदान में अनुपस्थित रही।

जापान के टोक्यो में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6 मापी गई; कोई नुकसान नहीं

टोक्यो, एजेंसी। जापान के टोक्यो में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6 मापी गई। इसका केंद्र जमीन से 68 किलोमीटर गहराई में था। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं, वह जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार-बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा होता है। कंपन की आवृत्ति ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किमी के दायरे में झटका तेज होता है। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा।

पनामा पेपर्स से जुड़े मामले में नवाज के बेटों को राहत; आरक्षित सीटों को लेकर कोर्ट से इमरान को झटका

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार को बड़ी राहत देते हुए एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने गुरुवार को पनामा पेपर्स घोटाले से जुड़े मामलों में नवाज शरीफ के बेटों की गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि 2016 के पनामा पेपर्स घोटाले में नाम आने के बाद हसन नवाज और हुसैन नवाज ने 2018 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। बता दें कि पनामा पेपर्स से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में आरोप लगाए गए थे लेकिन वे कभी भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए, जिसने उन्हें भ्रगोड़ा घोषित कर दिया। इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत द्वारा सात मार्च को दोनों के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट को गुरुवार तक निलंबित करने के बाद दोनों भाई पाकिस्तान लौट आए। गुरुवार को हसन और हुसैन इस्लामाबाद स्थित अदालत में पेश हुए, जिसने दलीलें सुनने के बाद भ्रष्टाचार मामलों में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट को

रद्द कर दिया। अदालत ने 50,000 रुपये के मुचलके पर उनकी जमानत भी मंजूरी दी। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दोनों बेटों ने भी अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होने से छूट के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने सुनवाई शुरूवार तक के लिए स्थगित कर दी।



पिछले साल अक्टूबर में नवाज शरीफ ब्रिटेन में चार साल के आत्म निर्वासन के बाद पाकिस्तान लौट आए और एक कार्यवाही के बाद उन्हें सभी मामलों से बरी कर दिया गया था। पीएम इमरान-एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी द्वारा गठबंधन सरकार पर सहमति के बाद नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनाया गया था। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पाकिस्तान की शीर्ष अदालत ने गुरुवार को सुजी इतेहाद काउंसिल(एसआईसी) द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। पाकिस्तान चुनाव आयोग

(ईसीपी) ने चार मार्च को सीट कोटा के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित सुजी इतेहाद काउंसिल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, साथ ही इसे नियमों का उल्लंघन बताया। बुधवार को पाकिस्तान के अर्ध-नियंत्रित मंसूर उस्मान अवान और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और ईसीपी के वकीलों ने अपनी दलीलें

पूरी कर ली थीं। एजीपी अवान ने कहा था कि एक राजनीतिक दल को आरक्षित सीटें तभी मिल सकती हैं, जब वह सामान्य सीट जीतेगी। पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील सिकंदर बशीर ने उनके तर्कों का समर्थन करते हुए कहा कि एसआईसी एक राजनीतिक दल है, लेकिन संसदीय नहीं।

पनामा पेपर्स से जुड़े मामले में नवाज के बेटों को राहत; आरक्षित सीटों को लेकर कोर्ट से इमरान को झटका

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के परिवार को बड़ी राहत देते हुए एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने गुरुवार को पनामा पेपर्स घोटाले से जुड़े मामलों में नवाज शरीफ के बेटों की गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि 2016 के पनामा पेपर्स घोटाले में नाम आने के बाद हसन नवाज और हुसैन नवाज ने 2018 में पाकिस्तान छोड़ दिया था। बता दें कि पनामा पेपर्स से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में आरोप लगाए गए थे लेकिन वे कभी भी अदालत के सामने पेश नहीं हुए, जिसने उन्हें भ्रगोड़ा घोषित कर दिया। इस्लामाबाद की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत द्वारा सात मार्च को दोनों के खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट को गुरुवार तक निलंबित करने के बाद दोनों भाई पाकिस्तान लौट आए। गुरुवार को हसन और हुसैन इस्लामाबाद स्थित अदालत में पेश हुए, जिसने दलीलें सुनने के बाद भ्रष्टाचार मामलों में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट को

पनामा पेपर्स से जुड़े मामले में नवाज के बेटों को राहत; आरक्षित सीटों को लेकर कोर्ट से इमरान को झटका

रद्द कर दिया। अदालत ने 50,000 रुपये के मुचलके पर उनकी जमानत भी मंजूरी दी। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दोनों बेटों ने भी अगली सुनवाई पर अदालत में उपस्थित होने से छूट के लिए आवेदन किया। कोर्ट ने सुनवाई शुरूवार तक के लिए स्थगित कर दी।